"लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा जाने वाला कागज।"

सं. 2–1/2007–एम.सी.(डी)
भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
*****

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE RAJYA SABHA
ON 13 AUG 2007

अधिप्रमाणित (हस्ताक्षर)
..... मंत्री
अल्पसंअनुबंधार्य मंत्री

# राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की 2005–2006 की तेरहवीं वार्षिक रिपोर्ट में समाहित सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन

| सिफारिश सं. | अध्याय, पैरा और रिपोर्ट की पृष्ठ सं. | सिफारिश का पाठ | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अध्याय 11, पैरा सं 11.1, पृष्ठ सं. 45 | सदन के दोनों सदनों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समयबद्ध प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिससे कि संसद सदस्य इस बात से अवगत हो सकें कि आयोग ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्या–क्या कार्य किए हैं। | इसे नोट कर लिया गया है |
| 2 और 3 | अध्याय 11, पैरा संख्या 11.2 और 11.3 पृष्ठ 48 | **सिफारिश सं. 2**<br>जब तक शिक्षा का अधिकार बाध्यकारी नहीं बना दिया जाता तब तक संघ और राज्य सरकारों के शैक्षिक प्राधिकरियों को मुस्लिम समुदाय द्वारा बालिकाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने और उनके प्रबंधन में अड़चने पैदा नहीं करनी चाहिए। | अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें चलाने की स्वतन्त्रता है। यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो प्रभावित पक्ष इस मामले को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग के सामने ला सकता है।<br>इसके साथ–साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि जैसे |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ऐसे विद्यालयों को अल्पसंख्यक स्तर प्रदान करने में उदारता बरती जाए तथा उक्त संस्थाओं में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए तथा वहां के स्टॉफ को वेतन का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।<br><br>**सिफारिश सं. 3**<br><br>अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए तैयार किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों का विस्तार मुस्लिम समुदाय तक किया जाना चाहिए। मुस्लिम बहुल जिलों में अच्छे स्तर के सरकारी विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जहां मुस्लिम बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। मुस्लिम बालिकाओं के बीच विद्यालय स्तर पर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष उपाय किए जाने चाहिए। | निकायों में अल्पसंख्यक कक्षों की स्थापना की गई है। ये अल्पसंख्यक कक्ष, संस्थान में, इस संबंध में जो कुछ समस्याओं का सामना कर रहे है, उनके समाधान में यह कक्ष उनकी सहायता करने में समर्थ होगा। सरकार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों सहित सभी समुदायों के लिए शैक्षिक विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी कर रही है और उस सीमा तक, जिसमें अल्पसंख्यक भी लाभ प्राप्त करने वालों का भाग है, और वे उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं।<br>अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवाओं की योजना, विद्यालयी शिक्षा तक पहुँच में सुधार, उर्दू पढ़ाने के लिए अधिक संसाधन प्रदान करने, मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण करने, अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक ढ़ांचे में सुधार करने के द्वारा समान उपलब्धता के माध्यम से शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर बल देता है।<br>इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने आधुनिक विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम लड़कियों सहित अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की है :–<br>(i) लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में उच्च प्राथमिक स्तर पर की जा रही है, जिसमें अनु०जाति/अनु०जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत सीटें होती है, अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों में ऐसे 210 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को मंजूरी दी गई है ; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (ii) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान ने 2003–04 में अल्पसंख्यकों की मेधावी छात्राओं के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है।<br>(iii) उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु 20,000 योग्यता एवं साधन आधारित छात्रवृत्ति की नई योजना शुरू की जा रही है।<br>(iv) सर्वशिक्षा अभियान और सामुदायिक पॉलीटेक्निक भी महिलाओं के शैक्षिक विकास पर विशेष बल देते है।<br>(v) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक रूप कमजोर वर्गों के लिए सघन क्षेत्र और मदरसा आधुनिकरण कार्यक्रम भी लड़कियों की शिक्षा पर बल देता है।<br>(vi) लड़कियों में विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत लड़कियों के लिए हॉस्टल सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक योजना कार्यान्वित कर रही है और स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक संस्थान भी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।<br>(vii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों द्वारा लड़कियों के हॉस्टलों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। |
| 4 | अध्याय 11, पैरा सं 11.4, पृष्ठ सं. 49 | आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके मुस्लिम बालिकाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था किए जाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं को इग्नू तथा अन्य मुक्त | मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में पहले ही आधुनिक इंटरएक्टिव संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है।<br>इसके साथ, मदरसों में आधुनिक विषयों को आरम्भ करने की योजना को संशोधित किया जा रहा है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा शामिल |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | विश्वविद्यालयों से सबद्ध करने की संभावना का गहनता से पता लगाए जाने की आवश्यकता है। | करने और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान तथा राज्य मुक्त विद्यालयों को मदरसों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है ताकि लड़कियों सहित मदरसों से निकलने वाले बच्चे व्यावसायिक कौशलों को मन में बैठा सके और यदि आवश्यक हो तो अपनी प्राइमरी स्तर की शिक्षा को आगे माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों तक जारी रख सकें। |
| 5 | अध्याय 11, पैरा सं 11.5, पृष्ठ सं. 49 | मुस्लिम बालिकाओं के लिए विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विज्ञान की शिक्षा के विकास की स्कीम कार्यन्वित की जा रही है। जिसमें हाशिए पर गुजर–बसर कर रहे इस समुदाय के संबंध में भी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। | विज्ञान शिक्षा में सुधार की योजना को अब राज्य क्षेत्र में अंतरित कर दिया गया है।<br>मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम में विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति तथा विज्ञान उपकरणों की आपूत्ति के लिए सहायता का प्रावधान है। इसमें लड़कियों सहित मुसलमानों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने तथा पुस्तकालयों की स्थापना के लिए भी सहायता का प्रावधान है। |

File No.2-1/2007(MC-D)
Government of India
Ministry of Minority Affairs

"Paper to be laid on the Table of Lok/Rajya Sabha.
AUTHENTICATED
New Delhi (Signature)
Date the Minister of Minority Affairs

**Annexure-I**

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE RAJYA SABHA ON 13 AUG 2007

**ACTION TAKEN MEMORANDUM ON THE RECOMMENDATION CONTAINED IN THE 13TH ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES FOR THE PERIOD FROM 2005 TO 2006**

| Recommendation | Chapter, Para and page of the Report | Text of the Recommendation | Action Taken |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Chapter 11, Para 11.1, Page-45. | A time bound system should be evolved for laying the Annual Reports of the National Commission for Minorities in both Houses of Parliament so that the Members of Parliament may know what the Commission has done for the minority communities. | Noted. |

File No.2-1/2007(MC-D)
Ministry of Minority Affairs

| 1. | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 &3 | Chapter 11, Paras 11.2 & 11.3, page-45. | Recommendation No.2<br><br>Until right to education becomes enforceable, the educational authorities of the Union and State Governments should not create hurdles in setting up of and managing the girls schools by the Muslim community. Minority status to such schools should be granted liberally and financial assistance for supply of textbooks and paying salaries to the teaching staff of such institutions should be provided by the Government.<br><br>Recommendation. No.3<br><br>Educational programmes for the development of SCs and STs should be extended to the Muslim community as well. Good quality government schools providing free education to Muslims girls should be set up in districts of high Muslim concentration. Special measures should be taken to promote modern school education for Muslim girls. | Minorities have freedom to establish and administer educational institutions of their choice. If this right is infringed/violated, the matter could be brought before the National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) by the affected parties.<br>Further, Minority Cells have been set up in bodies like All India Council for Technical Education(AICTE), University Grants Commission(UGC), Central Board of Secondary Education(CBSE), etc. The Minority Cells in these institutions will be able to help the minority institutions overcome some of the problems they are facing in this respect. The Government is also implementing educational development programmes for all communities including SCs/STs and minorities and to the extent the minorities form part of the clientele they are benefiting from them.<br>The Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities focuses on enhancing opportunities for education through equitable availability of Integrated Child Development Services (ICDS) scheme, improving access to school education, providing greater resources for teaching Urdu, modernizing Madarasa education, providing scholarships for meritorious students from minority communities and improving educational infrastructure through the Maulana Azad Education Foundation.<br>Besides, the Central Government has initiated the following schemes which are meant for minorities, including |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Muslim girls, to promote modern school education among them:-<br><br>(i) Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV) are being set up for girls at upper primary level in educationally backward blocks of the country where a minimum 75% seats are for SC/ST/OBC/Minorities; 210 KGBVs have been sanctioned in minority dominated blocks;<br>(ii) Maulana Azad Education Foundation (MAEF) has launched a scholarship scheme for meritorious girl students belonging to minorities in 2003-04.<br>(iii) A new programme of 20,000 merit-cum-means based scholarship scheme to encourage students belonging to minorities to pursue higher studies is being launched.<br>(iv) The Sarva Siksha Abhiyan(SSA) and Community Polytechnics also give special emphasis on educational upliftment of women.<br>(v) The Area Intensive and Madarsa Modernization Programme for Educationally Weaker Section of minority also emphasizes on girls' education.<br>(vi) For promoting modern school education among girls, Government is implementing a scheme for providing hostel facilities for girls studying in secondary and higher secondary schools and voluntary agencies are being given grant. Minority institutions are also availing of the facility. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (vii) The University Grants Commission is also providing financial assistance to set up girls hostels by minority educational institutions. |

| 1. | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4 | Chapter 11, Para 11.4, page 46 | Distance education for Muslim girls using modern communications technology needs particular attention. The possibility of linking up IGNOU and other open universities with Muslim educational institutions for girls needs to be seriously explored. | The Maulana Azad National Urdu University is already using modern Interactive Communication Technology (ICT) in its distance education programme.<br>Further, the scheme for introducing modern subjects in Madarasas is being revised. It is proposed to include vocational education and link up the National Institute of Open Schooling and State Open Schools with the Madarssas so that students, including Muslim girls, coming out of Madarasas can inculcate vocational skills and if needed continue their education beyond upper primary level into secondary and higher secondary levels. |
| 5 | Chapter 11, Para 11.5 & 11.5 | Science education needs to be promoted among Muslim girls. For this purpose, the scheme of improvement of science education being implemented by the Ministry of HRD should have a specific component for this marginalized group. | The scheme for improvement of science education has since been transferred to the state sector.<br>The Madarasa Modernization Programme provides assistance for appointment of science teachers and for supply of science kits. It also provides for help to set up libraries and promotes science education among Muslims, including Muslim girls. |